अध्याय 11

राजस्थान का सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास

मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है।

हमारा राजस्थान

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 342239 वर्ग किलोमीटर है। कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं अन्य कारण राजस्थान के विकास में बाधक रहे हैं। फिर भी राजस्थान समग्र विकास के पथ पर अग्रसर है। राजस्थान के विकास हेतु सरकार द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा, सड़क ,जल, कृषि, उद्योग, प्रौद्योगिकी, परिवहन आदि क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि, उद्योग, सेवाओं के साथ–साथ आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में निरन्तर प्रगति हो रही है। इस पाठ में हम राजस्थान के विकास को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत समझ सकते हैं–

1. सामाजिक विकास
2. आर्थिक विकास
3. प्रौद्योगिकी विकास

सामाजिक विकास

सामाजिक विकास से संबंधित विभिन्न घटकों, जैसे– शिक्षा, चिकित्सा, आवास, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छता आदि के विकास हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से विकास के सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान के सामाजिक विकास को हम निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत समझ सकते हैं–

(1) शिक्षा और साक्षरता– शिक्षा सही मायनों मे विकास के महत्वपूर्ण अंशदायी कारकों मे से एक है। शिक्षा लोगों की उत्पादकता और रचनात्मकता में वृद्धि करती है और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देती है।

राजस्थान राज्य के गठन के बाद से ही राज्य सरकार शैक्षिक संसाधनों का विकास करके शिक्षा का विस्तार कर, राज्य के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के ठोस प्रयास कर रही है। राज्य सरकार विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं, जैसे–सतत् शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और साक्षर भारत मिशन आदि के माध्यम से सम्पूर्ण साक्षरता और गुणवतापूर्ण शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है।

राज्य में साक्षरता के प्रतिशत में लगातार वृद्धि हो रही है। सन् 1951 में राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 8.02 था जो 2011 में बढ़कर 66.17 प्रतिशत हो गया है। राज्य में महिला शिक्षा के विस्तार के लिये अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आज बच्चों के निकटतम स्थान पर विद्यालय और पर्याप्त मात्रा में महाविद्यालय भी उपलब्ध हैं। राज्य में 'निःशुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से लागू किया गया है जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक–बालिका के लिये प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। यह अधिनियम शिक्षा के सार्वजनीकरण का सशक्त माध्यम बना है।

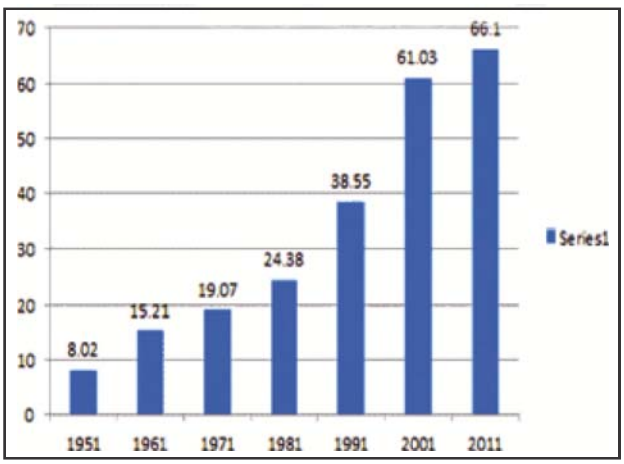

साक्षरता में राजस्थान की प्रगति

राजस्थान में महिला एवं पुरूषों की साक्षरता दर		
वर्ष	**महिला**	**पुरूष**
1951	2.51	13.09
1961	5.82	23.71
1971	8.46	28.74
1981	11.42	36.30
1991	20.44	54.99
2001	44.34	54.99
2011	52.10	79.20

राजस्थान की साक्षरता दर

शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण सार्वजनीकरण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय योजना प्रारम्भ की गई है। इन विद्यालयों में अधिक से अधिक शैक्षिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वजनीकरण की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि के लिए स्टेट इनिशिएटिव फोर क्वालिटी एजुकेशन (एस.आई.क्यू.ई) कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य– सरकार ने गरीब से गरीब व्यक्ति और दूरस्थ क्षेत्रों में भी सस्ती व गुणवत्तापुर्ण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ करवाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के

फलस्वरूप राज्य में मृत्यु–दर तथा मातृ व शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जाँच योजना, जननी–शिशु सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। '108 निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा' व '104 निःशुल्क सेवा' तथा जननी एक्सप्रेस योजना के उपलब्ध होने से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच जन साधारण तक हो गई है।

(3) आवास व खाद्य सुरक्षा– मुख्यमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के माध्यम से आवासहीन गरीब परिवारों को सस्ता आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत सरकार शौचालयहीन घर वाले गरीब परिवारों को शौचालय निर्माण करवाने के लिए सहायता दे रही है। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजित किए जा रहे हैं।

गतिविधि–
शिक्षक की सहायता से अपने आस–पास रहने वाले परिवारों में निरक्षर एवं कभी विद्यालय नहीं जाने वाले लोगों की सूची बनाइये एवं कारणों को जानकर कक्षा में चर्चा कीजिये।

आर्थिक विकास

हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि एवं ग्राम आधारित है। लगातार पड़ने वाले अकाल एवं सूखे की वजह से राजस्थान की गिनती पिछड़े राज्यों में की जाती थी। राज्य की अर्थव्यवस्था के सुनियोजित विकास को बढावा देने तथा उद्योगों के तीव्र विकास हेतु प्रारम्भ से ही राज्य सरकारें एवं निजी क्षेत्र गम्भीर एवं समर्पित रूप से प्रयासरत रहे हैं। राज्य संगमरमर, खनिज, तांबा, जस्ते की खानों और नमक के भण्डारों के लिये प्रसिद्ध है। राज्य में मुख्यतः खनिज और वस्त्र आधरित उद्योग हैं। राजस्थान देश का द्वितीय सबसे बड़ा पोलिएस्टर फाइबर और सीमेन्ट का उत्पादक राज्य है।

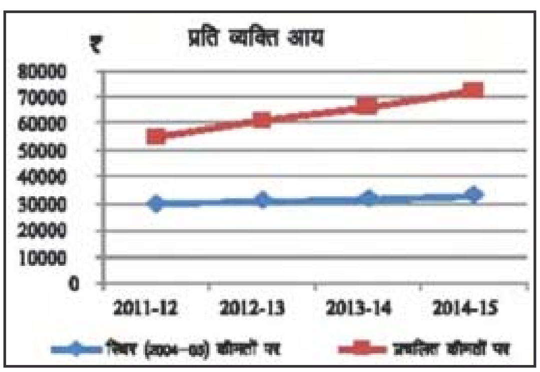

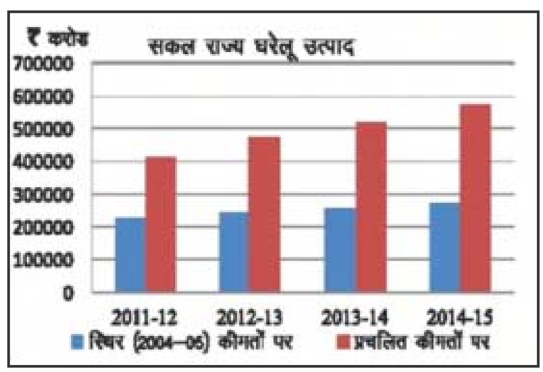

उद्योग विभाग द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास, हस्तकला उद्योगों के विकास एवं औद्योगिक गतिविधियों के संचालन में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने और उद्योगों को सहायता तथा सुविधाएँ उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। उद्योगों की स्थापना व अन्य आवश्यक सुविधाएँ व सहायता

उपलब्ध कराने हेतु राज्य में वर्तमान में 36 जिला उद्योग केन्द्र एवं 7 उप केन्द्र कार्यरत हैं। निवेष संवर्द्धन ब्यूरो (बी.आई.पी.) राज्य सरकार एवं निवेशकों के मध्य एक समन्वयक की भाँति कार्य करते हुए परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिलवाने हेतु तथा समस्याओं के निराकरण हेतु सेवाएँ प्रदान कर रहा है। अधिक निवेश को आकर्षित करने एवं विभिन्न योजनाओं में नीति सम्बन्धी सहयोग के लिये उद्योग विभाग ने ''अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम'' के साथ नॉलेज पार्टनरशिप समझौता किया है।

खनिज एवं उद्योग : राज्य में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, जैसे– जैव प्रौद्योगिकी, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, चमड़ा, कपड़ा, परिशुद्ध घटक, गृह उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.),सौर ऊर्जा एवं ऑटोमोबाइल उद्योगों के विकास में तेजी लाने के लिये रीको द्वारा विशिष्ट पार्क यथा–एग्रो फूड पार्क, नीमराना में जापानी पार्क आदि विकसित किये गये हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिये ये सभी उपाय अभिनव एवं प्रभावी हैं।

कपड़ा उद्योग

ऊर्जा : 1947 में केवल कुछ ही शहर ऐसे थे जिनको बिजली मिलती थी। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों तक विद्युत की पहुँच के कारण आज स्थिति बहुत भिन्न है। इस विषय में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विद्युत ऊर्जा उत्पादन की मुख्य प्रयोजनाओं में राजस्थान आण्विक ऊर्जा परियोजना–रावतभाटा ; कोटा और सूरतगढ़ तापीय परियोजनाएँ ; धौलपुर गैस आधारित तापीय परियोजना ; माही जल विद्युत परियोजना है। भाखड़ा, व्यास, चम्बल और सतपुड़ा अन्तरराज्यीय भागीदारी वाली परियोजनाएँ हैं। केन्द्रीय सेक्टर से राज्य को सिंगरोली, रिहन्द, अन्ता, औरेया, दादरी गैस संयंत्र, टनकपुर, उरी हाइड्रल परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त हो रही है। राजस्थान में ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्रों में वृद्धि होती जा रही है। बाड़मेर एंव जैसलमेर जिलों में पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त होने से राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है।

सौर उर्जा संयत्र

गतिविधि–

ऊर्जा के परम्परागत व गैर परम्परागत स्रोतों की तालिका बनाइए।

जयपुर मेट्रो

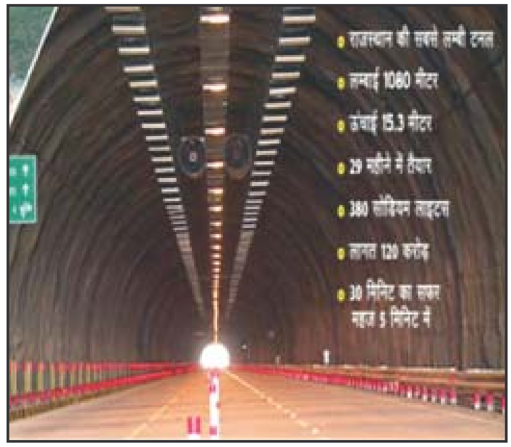

बूंदी टनल (सुरंग)

परिवहन : राज्य में सड़कों व रेल मार्गों का विस्तार हुआ है तथा परिवहन के साधनों में वृद्धि होती जा रही है। एक्सप्रेस हाईवे और मेगा हाईवे का विस्तार होता जा रहा है। बड़ी व विद्युतिकृत रेल लाईनों के विस्तार का कार्य प्रगृति पर है।

राज्य में उद्योगों के विकास हेतु नई निवेश प्रोत्साहन नीति जारी की गई है। दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (डी.एम.आई.सी.) का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान राज्य से होकर गुजरेगा। इस कॉरीडोर के विकास के साथ ही राज्य में औद्योगिक विकास को नए पंख लग जाएँगे। राज्य में निजी निवेष के प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर निवेश प्रोत्साहन सम्मेलन आयोजित कर उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा ही एक सम्मेलन 'रिसर्जेण्ट राजस्थान' 19 व 20 नवम्बर 2015 को जयपुर में आयोजित हुआ जिसमें देश–विदेश के अनेक बड़े उद्योगपति सम्मिलित हुए। उन्होंने राजस्थान में पूँजी निवेश करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ खरबों रुपयों के निवेश समझौते किए हैं। इस निवेशों के साकार होने पर राजस्थान की काया पलट हो जाएगी।

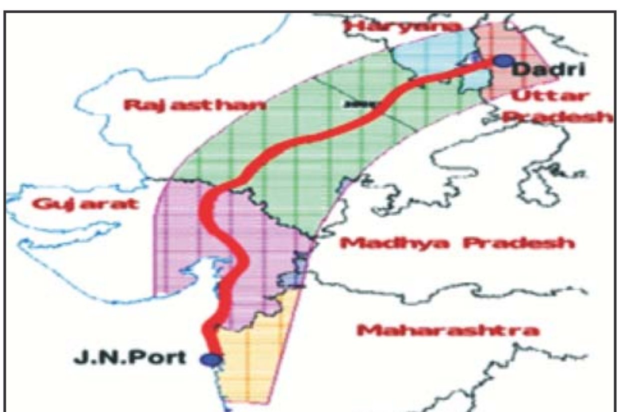

दिल्ली–मुम्बई कॉरीडोर योजना

दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (DMIC)

दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.) परियोजना के अन्तर्गत इस योजना में शामिल किए गए क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक नगर, आबादी क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, ऊर्जा संयंत्र, नॉलेज सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट व अन्य परिवहन सेवाएँ और अन्य सम्बद्ध सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं और डी.एम.आई.सी.विकास निगम के माध्यम से 1000 मेगावाट क्षमता के गैस आधारित पावर प्लान्ट व कौषल विकास केन्द्रों को विकसित करने के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। प्रथम चरण में खुशखेड़ा–भिवाड़ी– नीमराणा क्षेत्र में निवेश कर विकास किया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी विकास

कम समय एवं कम खर्च में प्रकृति में निहित संसाधनों के उपयोग के तरीके खोजना प्रौद्योगिकी विकास कहलाता है। किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ के प्रौद्योगिकी विकास से जाना जा सकता है। क्षेत्र के कच्चे माल एवं संसाधनों का उपयोग तकनीकी विकास पर निर्भर करता है।

राजस्थान में प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए 'राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय' की स्थापना की गई है। अनेक इंजिनियरिंग और प्रबंधन महाविद्यालयों की स्थापना हुई है। इन संस्थानों में राजस्थानी युवा बड़ी मात्रा में तकनीकी और प्रबंधन की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। फलस्वरूप राज्य में तकनीकी व प्रबंधन में दक्ष लोगों की उपलब्धता बढ़ती जा रही है, जो कि विकास की एक मुख्य जरूरत है। राज्य में 'सूचना प्रौद्योगिकी पार्क' एवं 'नॉलेज कॉरीडोर' की स्थापना की योजनाओं पर भी कार्य हो रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार द्वारा राजकीय विभागों में ई–गवर्नेन्स की सफलता सुनिश्चित करने के लिये राजकीय अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। आधार कार्ड योजना में पंजीकरण करवाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार राज्य में निवास के समीप राजकीय सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु राज्य में 11000 से अधिक ई–मित्र कियोस्क कार्यरत हैं। राजकीय सेवाओं से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने एवं जनता की शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से राजस्थान सम्पर्क पोर्टल www.sampark.rajasthan.gov.in का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

राजस्थान में विकास हेतु वर्तमान में नई उर्जा नीति, नवीन खनिज नीति, पर्यटन नीति बनाई गई है। राजस्थान में निवेश को आमन्त्रित करने के प्रयास हो रहे हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार सम्भावना है। जोधपुर, नागौर, बीकानेर में सौर ऊर्जा तथा बाडमेर और जैसलमेर में तेल व गैस के भण्डारों के विकास से एवं दिल्ली–मुंबई इण्डस्ट्रीयल कॅारीडोर के एक बड़े भाग के राजस्थान से जुड़े होने से राज्य में विकास और रोजगार के नये अवसर पैदा हो रहे हैं।

गतिविधि

इस पाठ में आए हुए चित्रों तथा रेखाचित्रों के बारे में शिक्षक से जानकारी प्राप्त कर के कक्षा में चर्चा कीजिए ।

शब्दावली

1. प्रौद्योगिकी : उद्योग एवं तकनीक का सम्मिलित रूप
2. कोरीड़ोर : गलियारा
3. निवेश : किसी उद्योग या धंधे में लाभ प्राप्ति हेतु धन लगाना।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

(I) क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है–

(अ) पहला (ब) दूसरा (स) छठा (द) दसवाँ ( )

(ii) 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है–

(अ) 60.1 प्रतिशत (ब) 62.1 प्रतिशत

(स) 64.1 प्रतिशत (द) 66.1 प्रतिशत ( )

(iii) राज्य में 'निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' लागू किया गया–

(अ) 1 अप्रेल 2009 (ब) 1 अप्रेल 2010

(स) 1 अप्रेल 2011 (द) 1 अप्रेल 2012 ( )

(iv) राजस्थान में मेट्रो रेल शुरू हुई है–

(अ) जोधपुर में (ब) जयपुर में

(स) उदयपुर में (द) कोटा में ( )

2. सामाजिक विकास के आवश्यक घटक कौन–कौन से हैं?
3. राजस्थान में तीव्र आर्थिक विकास के लिये क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?
4. तकनीकी विकास के कोई दो उदाहरण दीजिए।
5. राजस्थान में कौन–कौन से उद्योगों का विकास हुआ है ?
6. प्रौद्योगिकी विकास पर टिप्पणी लिखिए।
7. राजस्थान में शिक्षा एवं साक्षरता पर टिप्पणी लिखिए।
8. राज्य के आर्थिक विकास पर एक निबन्ध लिखिए।